भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2164
01.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

मंथन शिविर की सिफारिशों का कार्यान्वयन

2164. श्री विजय बघेल:
श्री बिभु प्रसाद तराई:
श्री गोडम नागेश:
श्री खगेन मुर्मु:
श्री जगदम्बिका पाल:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय द्वारा 17 अप्रैल 2025 को आयोजित 'मंथन शिविर' की प्रमुख सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो शिविर के दौरान चर्चा किए गए छह विषयगत क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए क्या विशिष्ट पहल की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन पहलों को कार्यान्वित करने में समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय तंत्र के लिए कोई प्रणाली स्थापित की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): मंथन शिविर का आयोजन भारतीय रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र को मजबूत बनाने तथा विकसित भारत@2047 के समग्र उद्देश्य को प्राप्त करने में इसकी भूमिका को समझने के उद्देश्य से किया गया था। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने मंथन शिविर के एक भाग के रूप में इस क्षेत्र में विचार-विमर्श करने के लिए में छह प्रमुख विषयगत क्षेत्रों की पहचान की है।

'समग्र सरकारी' दृष्टिकोण के अनुरूप और अंतर-मंत्रालयी समन्वय तंत्र के एक भाग के रूप में, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों को इन विचार-विमर्शों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के तत्वाधान में राजस्व विभाग, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, औषध विभाग, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नीति आयोग जैसे मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ सीएसआईआर, भारतीय मानक ब्यूरो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और स्वायत्त संगठन इस विचार-विमर्श में शामिल हुए।

इन विचार-विमर्शों के दौरान, कई इनपुट प्राप्त हुए हैं, जिनकी जाँच की जा रही है। विभिन्न सरकारी विभागों और विभिन्न उद्योग संघों के साथ हितधारक परामर्श भी किया जा रहा है।

*****